राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 308

प्रगति

समाचार पत्र

जनवरी 2021

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

“ आवासीय कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए सततयोग्य आवासीय तकनॉलोजी “

3 आवासीय कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए सततयोग्य आवासीय तकनॉलोजी

विषय-सूची

8
डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस ने एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला

8
सीडीसी ने ग्रामीण विकास पर तथ्यों की जाँच और डेटा सत्यापन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

9
लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान संचार

11
जेंडर एकीकरण और परिचालनात्मक रणनीति की तैयारी पर मिशन स्टाफ के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

12
एनआईआरडीपीआर ने मनाया 72 वां गणतंत्र दिवस

12
कोविड-19 सहायता पैकेज (सीएपी) के तहत ओएलएम का मामला अध्ययन

13
संपूर्ण भारत में मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना की एक रूपरेखा

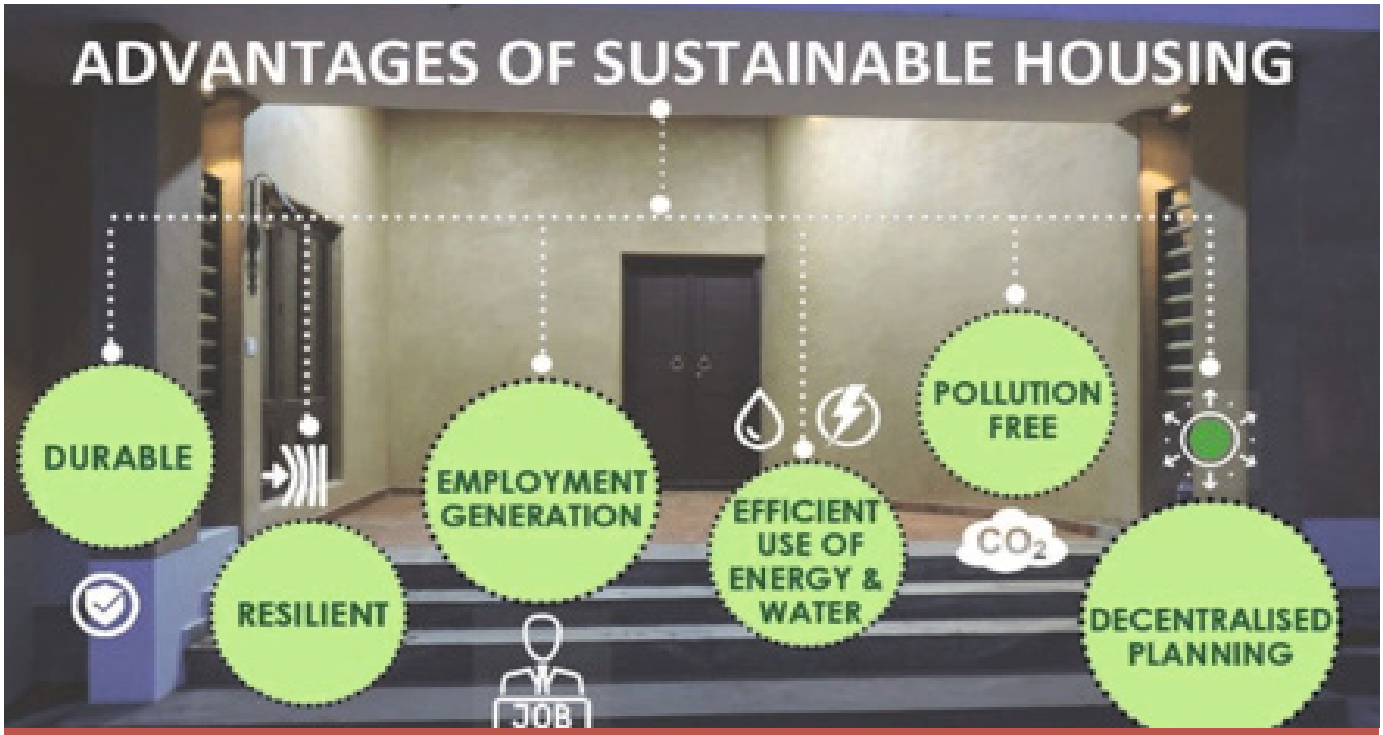

आवासीय कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए सततयोग्य आवासीय तकनॉलोजी

भारत में, लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ये 5 से 6 लाख गाँवों में रहती है तथा पूरे देश भर में फैली हुई हैं। इन परिवारों में से अधिकांश के मकानों की स्थिति बहुत खराब और दयनीय है। भारत में आवास पर 2011 के जनगणना आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के आधे से अधिक परिवार दयनीय आवास की स्थिति में रहते हैं। जनगणना के अनुसार, दयनीय आवास की स्थिति में रहने वाले ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या लगभग 140.5 मिलियन है। इस आंकड़े में वे परिवार शामिल हैं जो पक्की छत, दीवारों और फर्श, दो कमरे, परिसर के भीतर या बाहर पानी का आउटलेट, घरेलू बिजली कनेक्शन और एक शौचालय के बने घर में नहीं रहते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले परिवारों की सामाजिक श्रेणी में मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न-आय वर्ग के परिवार शामिल हैं। इन परिवारों की खराब आर्थिक स्थिति, जो मुख्य रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से हैं, वे अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए, ये परिवार अपने आवास की स्थिति में सुधार करने के लिए निवेश करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और परिणामस्वरूप वे खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहना जारी रखते हैं जो उनके स्वास्थ्य और समग्र सामाजिक जीवन को प्रभावित करता हैं।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 2022 तक ''सभी के लिए आवास'' सुनिश्चित करने के लिए स्वंय को प्रतिबद्ध किया है।

पारंपरिक निर्माण सामग्री की उच्च लागत और सततयोग्य कम लागत वाली आवासीय पद्धतियों पर तकनीकी जानकारी का अभाव, उन्हें पारंपरिक कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर करता है जो बाढ़, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों से ग्रस्त हैं। हाल के वर्षों में, यह पाया गया है कि गरीब परिवार जिनके पास पारंपरिक घर हैं, उन्हें भी बार-बार मरम्मत और रखरखाव की लागत को पूरा करना मुश्किल लगता है। सामग्री की उच्च लागत और पारंपरिक निर्माण तकनीकों के ज्ञान के साथ कुशल श्रम की अनुपलब्धता इन गरीब परिवारों के लिए अपने घरों को बनाए रखने के लिए इसे अक्षम्य बनाती है। कई जगहों पर, ग्रामीण कारीगर जैसे कुम्हार और बढ़ई जिनकी सेवाएँ गृह निर्माण के लिए आवश्यक हैं, वे अन्य लाभदायक व्यवसायों में स्थानांतरित हो गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसे आर्थिक स्थिति और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में समग्र सुधार के कारण ग्रामीण आवास निर्माण पैटर्न में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि, जो परिवार आवास में निवेश कर सकते हैं, वे कम लागत वाले आवास पर उचित जानकारी वाले प्रशिक्षित लोगों की अनुपलब्धता के कारण अपने घरों के संरचनात्मक घटकों को डिजाइन करने की प्रवृत्ति रखते हैं और कई बार आवास में पर्याप्त लागत खर्च करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता होती है । आधुनिक घर के मालिक होने की आकांक्षा देश के कई हिस्सों में एक सामाजिक आदर्श बन गई है। आवास कार्यक्रमों में शामिल एजेंसियों को आवासीय समाधान डिजाइन करते समय उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। बनायी गई आवास समाधान योजना एक ऐसे घर देने में सक्षम होना चाहिए जो मजबूत और लागत प्रभावी हो। इसलिए, इन पहलुओं की पेशकश करने की क्षमता वाले स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने की अधिक क्षमता है।

सततयोग्य आवास

सततयोग्य आवास वे हैं जिन्हें इस प्रकार डिज़ाइन, निर्मित और प्रबंधित किया जाता है:

- स्वस्थ, टिकाऊ और सुरक्षित
- आय स्तरों के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए किफायती
- पारिस्थितिक कम ऊर्जा और सस्ती निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग
- संभावित प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु प्रभावों को बनाए रखने के लिए व्यवहार्य
- सभ्य, सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा, जल, स्वच्छता और पुन: चक्रावर्तन सुविधाओं से लैस
- ऊर्जा और पानी का उपयोग कुशलता से करना और कुछ ऑनसाइट अक्षय ऊर्जा उत्पादन और जल पुन: चक्रावर्तन क्षमताओं से लैस
- पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना और बाहरी प्रदूषण से सुरक्षित रखना
- नौकरी, दुकानों, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल, शिक्षा और अन्य सेवाओं के संदर्भ में उपयुक्त रूप से अनुकूल।
- स्थानीय पड़ोस और व्यापक शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने-बाने को समुचित रूप से एकीकृत और उन्नत करना
- उचित रूप से संचालित और व्यवस्थित, समय पर पुनर्निर्मित और रखरखाव किया गया

Source: UN-Habitat

सततयोग्य आवासीय तकनॉलोजी का महत्व

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 2022 तक ''सभी के लिए आवास'' सुनिश्चित करने के लिए स्वंय को प्रतिबद्ध किया है। इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करना है। अनुमानित आवास लक्ष्य के लिए भारी मात्रा में निर्माण सामग्री और बुनियादी संरचना की आवश्यकता होगी। यह पारंपरिक निर्माण सामग्री के उपयोग से जुड़ी चिंताओं को दर्शाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं हैं। पारंपरिक निर्माण उद्योग में स्टील, सीमेंट, ईंटों और चूने के उत्पादन के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 80 प्रतिशत उत्पादन करने के अलावा, स्टील, सीमेंट, पेंट और ऊर्जा जैसे संसाधनों की भारी मात्रा में खपत होती है। अधिक मात्रा में ईंटों के उपयोग से कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ मिट्टी में भी कमी आएगी। यह इस संदर्भ में टिकाऊ भवन तकनॉलोजी का उपयोग जलवायु परिवर्तन और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अन्यथा पारंपरिक निर्माण तकनीकों और सामग्रियों के उपयोग के साथ होता रहेगा। इसके अलावा, आवास क्षेत्र में सरल और लागत प्रभावी टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ऊर्जा की व्यापक आवश्यकताओं को कम करने की काफी गुंजाइश है।

स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा गहन और गैर-नवीकरणीय पारंपरिक सामग्रियों के उपयोग के लिए एक विकल्प हो सकता है। इसी समय, वैकल्पिक ऊर्जा कुशल पारंपरिक सामग्री जैसे मिट्टी, थैच, लकड़ी की बड़े पैमाने पर आवश्यकता को पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए, आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम लागत वाली स्थायी इमारतों को तैयार करने के लिए उपलब्ध संसाधनों और तरीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है जो ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हैं। वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग सीमेंट और स्टील जैसी पारंपरिक सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले उच्च पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, फिलर स्लैब और फ़ेरोसीमेंट चैनल जैसे छत तकनॉलोजी को सीमेंट और स्टील के उपयोग में 25 से 30 प्रतिशत तक कम करने की सूचना है। चिनाई की दीवारों की लागत को कम किया जा सकता है क्योंकि रैट ट्रैप बॉन्ड चिनाई में उपयोग की जाने वाली ईंटों और मोर्टार की मात्रा 25 प्रतिशत कम हो जाती है। पारंपरिक इमारतों को हीटिंग और शीतलन आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए लगभग 50 प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टिकाऊ निर्माण तकनीकों को अपनाकर, उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री और सरल डिजाइन जैसे प्राकृतिक दिन के उजाले, वेंटिलेशन के उपयोग से उपयुक्त थर्मल इन्सुलेशन बनाने के साथ ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है।

क्रम सं.	भवन सामग्री की श्रेणी	ऊर्जा की तीव्रता (जीजे / टी)	उदाहरण
i)	बहुत उच्च ऊर्जा	> 50	एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, तांबा, जस्ता
ii)	उच्च ऊर्जा	5-50	सीमेंट, स्टील, कांच, कोलतार, विलयक, कार्डबोर्ड, कागज और सीसा
iii)	मध्यम ऊर्जा	1-5	चूना, जिप्सम प्लास्टर बोर्ड, जली हुई मिट्टी की ईंट, उन्नत वर्टिकल शाफ्ट भट्टी से जली हुई मिट्टी की ईट, मिट्टी सीमेंट ब्लॉक, वातित ब्लॉक, खोखले कंक्रीट ब्लॉक, जिप्सम प्लास्टर, कंक्रीट ब्लॉक, लकड़ी, लकड़ी बोर्ड, सेल्यूलोज इन्सुलेशन, इन-सीट कंक्रीट
iv)	कम ऊर्जा	> 1	रेत, कुल, फ्लाई ऐश, सीमेंट स्थिरीकृत अर्थ ब्लॉक, पुआल की गठरी, बांस, पत्थर।

APPROPRIATE ROOFING TECHNIQUES

FERRO CEMENT CHANNEL

Bricks casted into panels of size 1.10m x 0.50m between of reinforced concrete beams. Durable and provides good thermal insulation. Costs about 22% less than RCC slabs.

FILLER SLAB ROOF

FILLER SLAB ROOF

Filler materials like clay tiles, bricks, coconut shells, clay bowls are placed between reinforcement while concrete is poured. It enhances thermal comfort giving an aesthetic look. Costs about 25% less than RCC slabs.

BRICK PANEL ROOF

Tiles made like cones using burnt clay are used for roofing. It provides good thermal insulation. No steel, concrete, plastering and centering required. Local potters can get employment. Costs about 35 % less than RCC slabs.

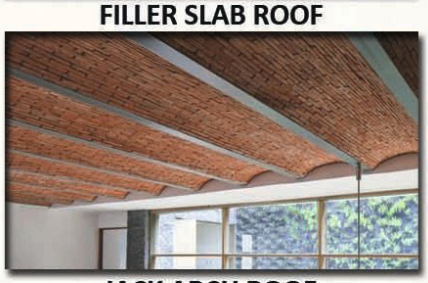

JACK ARCH ROOF

JACK ARCH ROOF

Bricks are used in form of arches between 2 beams or walls. No use of reinforcement and concrete. Aesthetic look and cost effective. Costs about 23% less than RCC slabs.

CONICAL CLAY TILE

Tiles made like cones using burnt clay are used for roofing. It provides good thermal insulation. No steel, concrete, plastering and centering required. Local potters can get employment. Costs about 35 % less than RCC slabs.

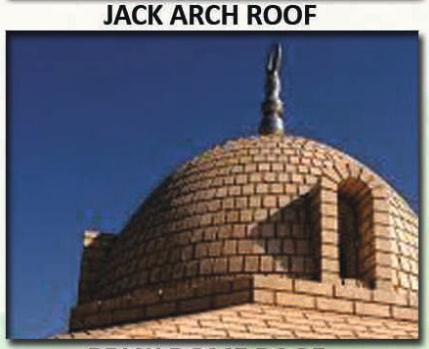

BRICK DOME ROOF

BRICK DOME ROOF

Bricks are arranged in layers using cement mortar 1:3 “brick on edge” for roof. No steel or concrete is used for the domes. Good thermal insulation and durable. Costs about 32% less than RCC slabs.

CONICAL GLASS CLAY TILE

FEROCEMENT CHANNEL

BRICK PANEL ROOF

PRE CAST CONCRETE SLAB

एनआईआरडीपीआर द्वारा सततयोग्य आवास पहल

भारत में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर) ने ग्रामीण तकनॉलोजी पार्क, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र (एनआरबीसी) स्थापित करने की पहल की है।

केंद्र का अधिदेश सततयोग्य आवास प्रौद्योगिकियों पर कौशल विकास केंद्र के रूप में कार्य करना है जो इंजीनियरों और राजमिस्त्री को ज्ञान और कौशल प्रदान करेगा। केंद्र विभिन्न एजेंसियों और पेशेवरों द्वारा सम्पूर्ण भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की सततयोग्य आवास तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, आवास क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों पर कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। केंद्र सामग्री की विविधता

के साथ लागत प्रभावी निर्माण प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला, निर्माण की पुरानी और नई तकनीकों का सम्मिश्रण करने वाली प्रौद्योगिकियों का परिचय कराता है । केंद्र में दिखाई गई तकनॉलोजी भूकंप, चक्रवात और आग जैसी आपदा उन्मुख स्थानों के लिए उपयुक्त है । इन संरचनाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और लोगों के कौशल का उपयोग करके बनाया गया है । निर्माण लागत उस विशेष स्थान पर पारंपरिक निर्माण के लागत की तुलना में 25 से 40 प्रतिशत कम होगी। लागत की भिन्नता मिट्टी की टाइपोलॉजी और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है।

केंद्र में प्रदर्शन उद्देश्य के लिए बनाए गए 15 टाइपोलॉजी घरों में 40 से अधिक सततयोग्य आवास प्रौद्योगिकी घटकों को शामिल किया गया है। ये सभी संरचनाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि वे ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के साथ निर्मित हैं। प्रदर्शन इकाइयां पीएमएवाई घरों, पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि के लिए सततयोग्य आवास तकनीकों का उपयोग करते हुए निर्मित विभिन्न मॉडल घरों को भी एनआरबीसी में प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा, देश भर में रुचि रखने वाले निजी दलों और सरकारी निर्माण कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता भी एनआरबीसी के इंजीनियरों द्वारा प्रदान की जा रही है। इस अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रकाशन तैयार किए गए हैं। एनआईआरडीपीआर में एनआरबीसी की स्थापना देश के विभिन्न हिस्सों में लागत प्रभावी टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए अधिक गुंजाइश देती है। इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की आवास की जरूरतों को सस्ती कीमत पर बढ़ाने और पूरा करने की उम्मीद है।

सततयोग्य आवासीय तकनॉलोजी को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ

1. भवन प्रदर्शनी इकाइयाँ: सततयोग्य आवास तकनीकों का उपयोग करते हुए देश भर में निर्मित भवनों की संख्या इस समय कम है। इसलिए, लोगों में इन तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश के हर ब्लॉक में स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी इकाईयों की एक महत्वपूर्ण संख्या बनाने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवनों और मॉडल पीएमएवाई घरों के निर्माण को टिकाऊ इमारत प्रौद्योगिकियों के स्थायित्व और लागत प्रभावशीलता का प्रदर्शन करने के लिए जोर दिया जाना चाहिए।

2. जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण: लोग बड़े पैमाने पर सततयोग्य निर्माण प्रौद्योगिकियों के फायदे और किफायती के बारे में नहीं जानते हैं। एक और बड़ी बाधा यह है कि यहां तक कि आवास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में शामिल इंजीनियरों और राजमिस्त्री जैसे प्रमुख अधिकारियों को सततयोग्य आवास प्रौद्योगिकियों की तकनीकों और लाभों के बारे में पता नहीं है। इसलिए, पर्याप्त संख्या में जागरूकता और परिचयात्मक कार्यक्रमों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है। स्थायी आवास पहलुओं से संबंधित भवन प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित इंजीनियरों और राजमिस्त्री की कमी एक

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर (फाईल फोटो)

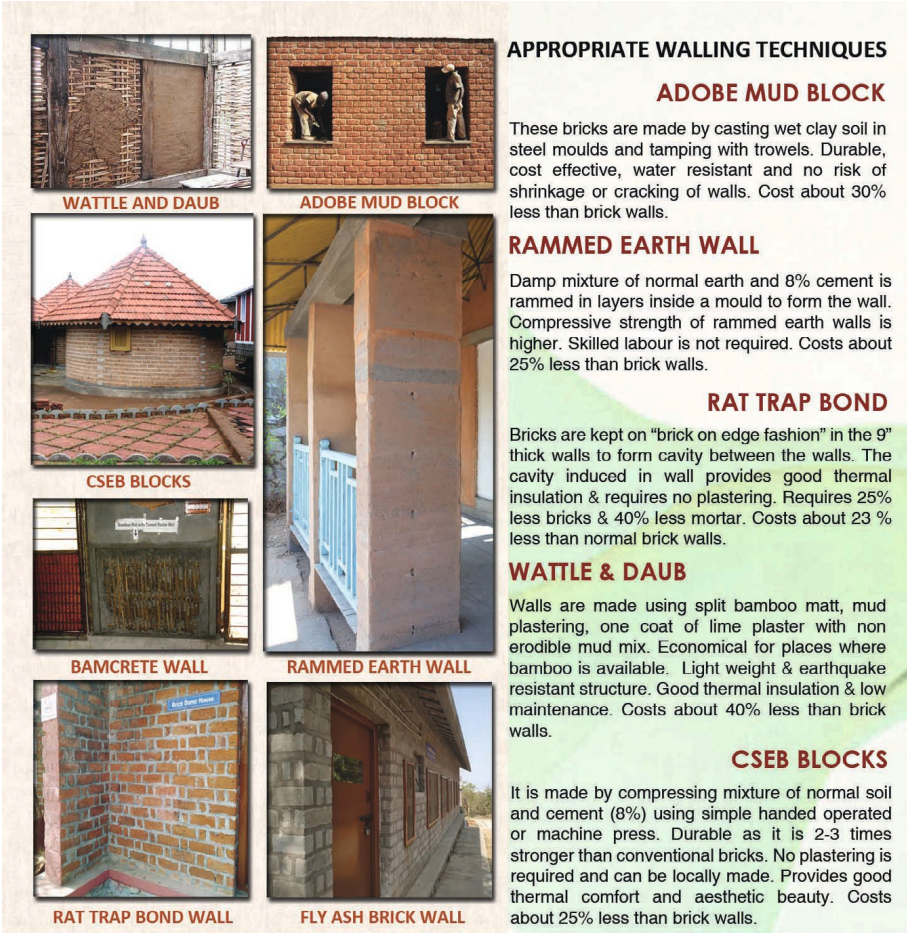

प्रमुख चिंता का विषय जिसे संबोधित किया जाना है। सरकारी कार्यकर्त्ताओं, बिल्डरों और वास्तुकार संघों के सहयोग से अच्छी तरह से डिजाइन की गई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ करना चाहिए।

3. दस्तावेज़ीकरण और संचार सामग्री: सरल और प्रभावी संचार सामग्री विकसित करना महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग लोगों सहित आवास क्षेत्र में शामिल प्रमुख हितधारकों में सततयोग्य आवास प्रौद्योगिकियों की अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सततयोग्य आवास प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रमुख संदेश देने के लिए उपयुक्त संचार रणनीतियों का विकास करना आवश्यक होगा। सामग्रियों में लिखित और वीडियो दोनों रूप शामिल हो सकते हैं।

4. उद्यमशीलता को बढ़ावा देना: निर्माण क्षेत्र का समर्थन करने वाले उद्यम मुख्य रूप से पारंपरिक निर्माण सामग्री का ही उत्पादन करते हैं। इसलिए, निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए तंत्र बनाने की तत्काल आवश्यकता है जो स्थायी आवास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं जैसे स्थिर मिट्टी के ब्लॉक, शंकुकार टाइल और फ्लाई ऐश ईंटें, आदि, ताकि ये स्थानीय रूप से आवास कार्यक्रमों से जुड़े लोगों और तकनीशियनों के लिए उपलब्ध हों।

जहां तक पीएमएवाई ग्रामीण आवास कार्यक्रम का संबंध है, पंचायतें आवश्यक सततयोग्य निर्माण सामग्री जो बाजार में उपलब्ध नहीं हैं का उत्पादन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जिससे ग्रामीण लोगों के लिए एमजीएनआरईजीएस कार्यक्रम के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करते है । इस पहलू को मॉडल पंचायतों में तैयार किया जा सकता है जो स्केलिंग के लिए उपयुक्त तंत्र पर पहुंचने के लिए देश भर में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं।

5. मानकीकरण और संहिताकरण: सततयोग्य भवन प्रौद्योगिकियों में कई तकनीक और विविधताएं हैं, जो कि स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनाया जा रहा हैं। हालाँकि, बहुत उपयोगी तकनीकों की संख्या को सीमित करना उचित होगा ताकि इनका मानकीकरण हो सके और इन्हें निर्माण क्षेत्र के मुख्यधारा में सक्षम बनाने के लिए बिल्डिंग कोड में कोडित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार द्वारा तैयार किए गए दरों के मानक अनुसूची (एसएसआर) में ऐसी मानकीकृत स्थायी आवास तकनीकों को शामिल करने का प्रयास किया गया है ताकि स्थानीय इंजीनियरों को आवास परियोजनाओं के लिए अपने आकलन तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके। वर्तमान में, एसएसआर में सततयोग्य आवास तकनीकों को शामिल करने की अनुपस्थिति में, कई इंजीनियर जो इन तकनीकों से अवगत हैं, वे अपनी परियोजनाओं में ऐसे घटकों को शामिल करने में सक्षम नहीं हैं।

6. ग्रीन रेटिंग और प्रोत्साहन: इस समय, आवास क्षेत्र में आवासीय भवनों के रेटिंग की व्यवस्था नहीं है और उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र नही है जो स्थायी आवास सिद्धान्तों का उपयोग करके अपने घरों के निर्माण में रुचि ले रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ढांचे के आलोक में सततयोग्य आवासीय घरों को बढ़ावा देने के सकारात्मक पक्ष पर विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। ग्रीन बिल्डिंग सिद्धान्तों वाले घरों जैसे कि पर्यावरण अनुकूल लागत बचत सामग्री, पानी और ऊर्जा बचत उपकरण, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, आदि का उपयोग, सरकार द्वारा सौर या जैव-ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन पर विचार किया जा सकता है। सततयोग्य भवनों के निर्माण पर विचार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में सततयोग्य भवन घटकों पर सब्सिडी या हाउस टैक्स या बिक्री कर में कमी की पेशकश लंबे समय तक काम कर सकती है।

डॉ. एस. रमेश सक्तिवेल
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी)
सुश्री आर. विष्णु प्रिया
युवा पेशेवर एवं वास्तुकार
सीआईएटी एवं एसजे, एनआईआरडीपीआर,
कवर पेज डिजाइन: **श्री वी.जी. भट्ट**

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस ने एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, ने 27 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

इससे पूर्व डॉ. जी. नरेंद्र कुमार ने अपर मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के रूप में कार्य किया है। उन्हें उस्मानिया विश्वविद्यालय से बायो केमिस्ट्री विषय पर पीएचडी तथा मैक्सवेल स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने बॉयो टेक्कनॉलोजी विषय में आईआईटी दिल्ली से एम.टेक पूर्ण किया और उस्मानिया विश्वविद्यालय से आर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी तथा वनस्पति शास्त्र में बीएससी डिग्री पूर्ण किया। डॉ. कुमार ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीजी डिप्लोमा किया है और सिरैक्युज़ विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है। डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार ने दिल्ली में चार विश्वविद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और उच्च शिक्षा की पहुँच को बढ़ाया है। इससे पहले उन्होंने भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, आईसीआरआईएसएटी और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में कार्य किया है।

सीडीसी ने ग्रामीण विकास पर तथ्यों की जाँच और डेटा सत्यापन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद द्वारा 29 जनवरी, 2021 को ग्रामीण विकास पर तथ्यों की जाँच एवं डेटा सत्यापन पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी), सीडीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक रही।

विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी), जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए), विभिन्न राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के सदस्यों और अन्य ग्रामीण विकास अधिकारियों के लिए तीन घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाचार और विचारों की अवधारणा को समझने किसी भी प्रकार के डेटा के लिए ऑनलाइन उपलब्ध सत्यापन उपकरण का उपयोग सीखने और सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना को पैदा करने की दृष्टि से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान गलत सूचना, समाचारों के हेरफेर, फर्जी समाचारों के प्रकार, सोशल मीडिया के उपयोग, ट्रोल की गई दृश्य सामग्री आदि पहलुओं पर लंबी चर्चा की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयुक्त प्रस्तुति से एक स्लाइड

डॉ. आकांक्षा ने विभिन्न मामला अध्ययन का उपयोग करके गलत सूचना के खतरों को सामने रखा। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गलत सूचना के प्रसार के खतरे से निपटने के लिए उठाए गए मौजूदा कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि चूंकि भारत लगभग 138 मिलियन लोगों की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए फर्जी खबरों का मुद्दा भारत जैसे धार्मिक रूप से विविध राज्य में एक अनूठा खतरा है।

डॉ. आकांक्षा ने नकली समाचारों को पहचानने के लिए विभिन्न युक्तियों पर भी चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने ऐसे उपाय सुझाए जो गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जा सकते हैं। अंत में, उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपने सीखने को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से गलत सूचनाओं को स्वीकार करने और फैलाने से रोकने में मदद करें। प्रतिभागियों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की और टीम से नियमित आधार पर ग्रामीण विकास अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया।

लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान संचार

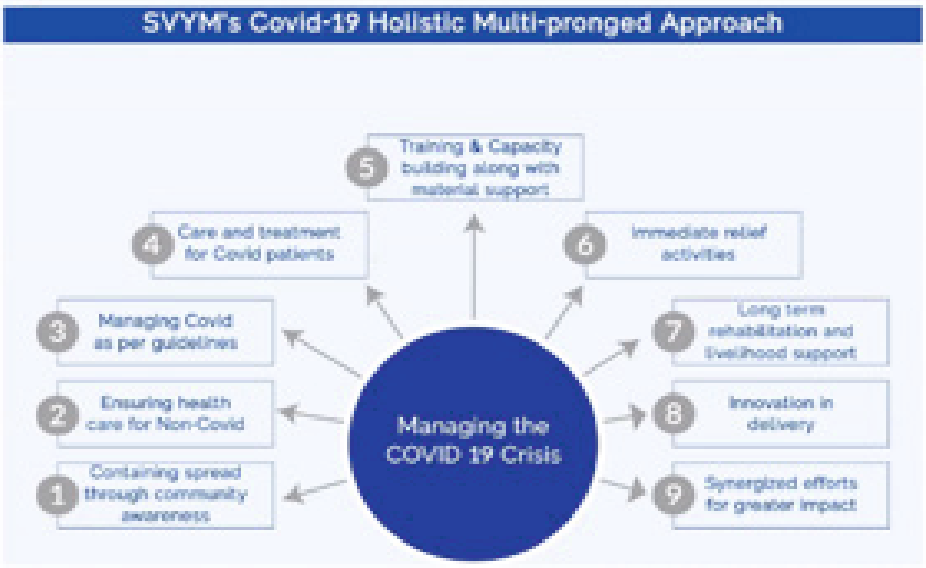

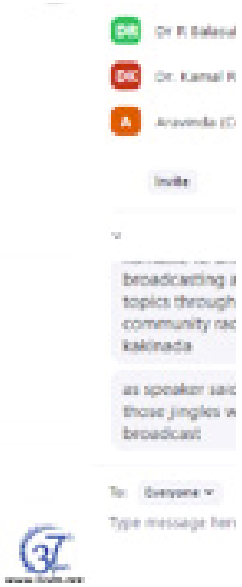

लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान संचार पर वेबनार के दौरान प्रस्तुत की गई एक स्लाइड

कोविड - 19 उपयुक्त व्यवहार पर जोर देने के साथ-साथ कोविड - 19 वैक्सीन के स्वागत का समर्थन करने के लिए संचार की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, संचार संसाधन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने यूनिसेफ हैदराबाद के क्षेत्र कार्यालय के सहयोग से 28 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान संचार पर अनुभव साझा करने के लिए एक वेबिनार आयोजित किया इस अवसर पर सरकार, सिविल सोसाइटी और विश्वास-आधारित संगठनों के प्रमुख हितधारकों को पैनल सदस्यों के रूप में कोविड - 19 प्रतिक्रिया पर अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया । कोविड - 19 के लिए जोखिम संचार और सामुदायिक सहभागिता पर प्रशिक्षित प्रमुख लाइन विभागों के अधिकारियों और अन्य हितधारकों को भाग लेने और पैनल के सदस्यों के अनुभवों से सीखने के लिए आमंत्रित किया गया था। वेबिनार में कोविड - 19 के लिए आरसीसीई पर अनुभवों और अध्यायों पर चर्चा की गई और आरसीसीई के लिए शासन, समुदायों के साथ कार्य करना, निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ काम करना, सत्यनिष्ठ नेताओं और नेटवर्क के माध्यम से संपर्क और आने वाले महीनों में कोविड - 19 वैक्सीन से संबंधित संचार के लिए दृष्टिकोण आदि को भी कवर किया गया ।

वेबिनार में छह विशिष्ट पैनलकर्ता थे:

- कोविड-19 उपयुक्त अभिव्यवहार (सीएबी) हेतु आरसीसीआई के लिए शासन, डॉ. कमलराज, सलाहकार - लोक स्वास्थ्य, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अनुभव

- समुदायों के साथ जुडाव - डॉ. बालासुब्रमणियम, संस्थापक, स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन द्वारा कर्नाटक के अनुभव

- डॉ. साई सुभाश्री राघवन साथी की कंट्री डायरेक्टर द्वारा सीएबी के प्रचार के लिए निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ काम करना

-

- बी.आर. वर्गीज थेकानाथ, निदेशक, मोनफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा मलिन बस्तियों में शहरी झुग्गी तक पहुँचना।

-

- यूएफईआरडब्ल्यूएएस के श्री बीटी श्रीनिवासन द्वारा वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद के निवासियों तक पहुँचना

-

- एसएसएसपी के राष्ट्रीय सेवा समन्वयक श्री सिरिपुरापु कोटेश्वर राव द्वारा सद्भावी नेताओं और नेटवर्क के माध्यम से संपर्क ।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों से कुल 78 प्रतिभागी उपस्थित हुए ।

डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी), सीआरयू ने वेबिनार में भाग लिया और सही समय पर कोविड-19 प्रतिक्रिया के अनुभवों को साझा करने के संबंध में वेबिनार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

जैसा कि कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी चल रही है, लोगों को स्वंय निर्धारित करने के लिए कि क्या सही और क्या गलत है पर सशक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है । सुश्री सीमा, यूनिसेफ से सी 4 डी विशेषज्ञ, एचएफओ ने सभी पैनल सदस्यों को निमंत्रण स्वीकार करने और वेबिनार में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आरसीसीई के प्रति सीआरयू और यूएनआईसीईएस के प्रति सीआरयू और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयासों पर एक विस्तृत प्रस्तावना प्रस्तुत की। यूनिसेफ के सी 4 डी परामर्शक श्री किशोर ने पैनल चर्चा का संचालन किया।

डॉ. कमलराज, सलाहकार-लोक स्वास्थ्य, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 उपयुक्त अभिव्यवहार (सीएबी) हेतु आरसीसीई के लिए शासन से प्राप्त अनुभव और सीख को साझा किया। उन्होंने कहा कि जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव एक लोक स्वास्थ्य उपाय है, जो जीवन को बचा सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आरसीसीई को अत्यधिक महत्व दिया और आरसीसीई गतिविधियों में नेतृत्व के उच्चतम स्तर को शामिल किया। उन्होंने 11 लाइन विभागों के प्रमुखों, जिला कलेक्टरों के साथ-साथ सीएसओ, एफबीओ के विभागाध्यक्षों के साथ काम किया है। महामारी के चरम से पहले, उन्होंने आरसीईसी के लिए शुरुआती महीनों में उच्च गति बनाई।

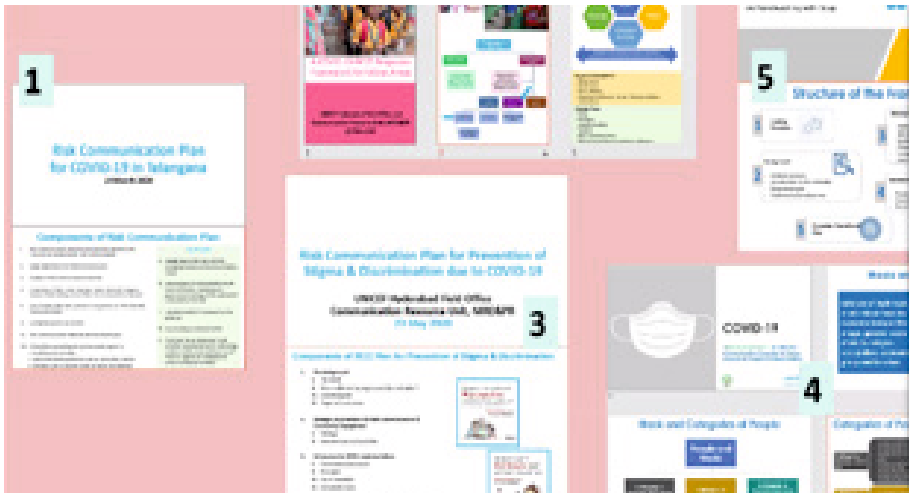

वेबिनार की एक स्लाइड

आरसीसीई पर जिलों के लिए अलग-अलग उपायों पर समय पर मार्गदर्शन और परिपत्र जारी किए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 360 डिग्री के संचार दृष्टिकोण को अपनाया और प्रसार के लिए सामग्री के विभिन्न प्रोटोटाइप और प्रदर्शन को जिले में समर्थन दिया गया। उन्होंने आरसीसीई के समवर्ती निगरानी पर एक उपकरण विकसित किया और उसे कार्यान्वित किया।

डॉ. बालसुब्रमणियम, संस्थापक, स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन ने कर्नाटक में कोविड-19 के दौरान समुदायों के साथ अपने अनुभवों के माध्यम से कार्य किया। कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों के अनुपालन के लिए समुदायों की मांग के बजाय उनका ध्यान उदात संदेश पर अधिक था। वे गैर-अभिहित दृष्टिकोण, भागीदारी को बढ़ावा देने और उत्पन्न समाधानों द्वारा समुदायों को भागीदार बनाने के लिए एक वातावरण बनाने में सक्षम थे। उन्होंने जोर दिया कि लोगों में संचार की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सेवाओं के साथ-साथ संचार को गुजरना होगा। यह पाया गया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव जमीनी स्तर के दर्शकों तक पहुंचने में अच्छा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका पर प्रख्यात व्यक्तियों के माध्यम से लेख, ब्लॉग, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

एसएसटीएचआई (साथी) के डॉ. सतीश कुमार ने बताया कि समुदायों में इन व्यवहारों को बनाए रखने के लिए सीएबी पर संचार को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, अन्यथा टीकाकरण पूरा होने के बाद लोगों के इन व्यवहारों को छोड़ देने की संभावना है। उन्होंने निजी अस्पतालों, फार्मेसियों और इन संस्थानों में की गई विभिन्न संचार गतिविधियों के अपने नेटवर्क के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कोविड-19 पर सामग्री और संदेश साझा करने के लिए व्यापक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया है। यह कहा गया कि निजी अस्पताल आसानी से भाग लेने के लिए सहमत हुए और अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का स्वागत किया क्योंकि वे अधिक कमजोर थे, यह कोविड-19 वैक्सीन संचार के लिए उपयोगी होने का एक बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने जाने-माने डॉक्टरों से टीकाकरण के लिए समर्थन जुटाने और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रेरित करने में साथी के समर्थन का आश्वासन दिया।

एमएसआई के भाई वर्गीज ने अपनी गतिविधियों के बारे में साझा किया जिसमें कोविड-19 निवारक संदेशों के साथ शहरी मलिन बस्तियों तक पहुंचना शामिल था। यह कहा गया कि कोविड-19 के संदर्भ में शहरी मलिन बस्तियां सबसे कठिन परिदृश्य थीं। सोशल सामाजिक दूरी बनाए रखना और हाथ धोना एक बड़ी चुनौती थी या मलिन बस्तियों में लगभग असंभव था। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में उन्होंने लॉकडाउन के 3 दिन से राहत सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया और समुदायों में एमएसआई के प्रति बहुत अच्छा विश्वास स्थापित किया। उनके पास स्थानीय समुदायों के स्वयंसेवक थे जो जागरूकता गतिविधियों को करने के लिए तैयार थे, उनकी स्थानीय उपस्थिति और मलिन बस्तियों की समझ के कारण अच्छे परिणाम मिले थे। लॉकडाऊन के दौरान घरेलू नौकरों के भेदभाव को आरडब्ल्यूएएस के साथ हल किया गया।

यूएफईआरडब्ल्यूएएस के श्री श्रीनिवास ने आरडब्ल्यूएएस के साथ हैदराबाद में अपने नेटवर्क में किए गए रोचक कार्य को प्रस्तुत किया। वे निवासी कल्याण संघों के साथ लगे हुए थे, सीएबी पर जागरूकता पैदा की, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कलंक और भेदभाव को संबोधित किया, स्वास्थ्य विभाग के साथ वकालत की और गेटेड समुदायों में संगरोध केंद्र का समर्थन करते हुए, परीक्षण केंद्रों की निगरानी, नियंत्रण कक्ष, पीपीई / स्वच्छता किट की आपूर्ति, लॉकडाऊन के दौरान एनजीओ भागीदारों के माध्यम से प्रवासियों और शहरी मलिन बस्तियों के लिए राहत कार्य किए। परीक्षण केंद्रों के लिए आरडब्ल्यूएएस सामुदायिक हॉल का उपयोग किया गया।

श्री कोटेश्वर राव, राष्ट्रीय सेवा समन्वयक, सत्य साई सेवा संगठन ने सद्भावी नेताओं और नेटवर्कों के माध्यम से संपर्क प्रस्तुत किया, जिसे सत्य साईं सेवा संगठन के स्वयंसेवकों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में किया। उन्होंने कहा कि रोकथाम और संरक्षण एसएसएसओ का जुड़वां दृष्टिकोण था। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों (22 लाख खाद्य पैकेट), सामुदायिक रसोई - 37 लाख मिल्स पकाए गए और परोसे गए, स्वच्छता किटों का उत्पादन और वितरण किया। मनो-सामाजिक समर्थन वाले लोगों की सहायता के लिए 2,000 से अधिक व्हाट्सएप समूहों पर प्रेरक और सकारात्मक संदेश भेजे।

पैनल के सदस्यों ने प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सवालों को संबोधित किया। यूनिसेफ की सी4डी विशेषज्ञ सुश्री सीमा ने सभी पैनल सदस्यों को धन्यवाद दिया और कोविड-19 वैक्सीन संचार में संगठनों से इसी तरह के समर्थन और उत्साही कार्य हेतु अनुरोध किया। उन्होंने टीका संचार के लिए पैनल चर्चा से हटाए गए कार्रवाई बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया:

- 360 डिग्री अभिसंचार दृष्टिकोण
- सामुदायिक रेडियो और सेल फोन बड़ी योजना के भाग के रूप में अभिसंचार के लिए मजबूत उपकरण हैं
- लेख, वैक्सीन की विश्वसनीयता पर प्रख्यात व्यक्तित्वों के ब्लॉग और इसे सोशल मीडिया में प्रसारित करना, आदि।
- सीएबी पर संचार को बनाए रखने की जरूरत है
- निजी अस्पताल टीका संचार के लिए अच्छा मंच हैं
- सोशल मीडिया पर नकारात्मक संदेश प्रबंधन

जेंडर एकीकरण और परिचालनात्मक रणनीति की तैयारी पर मिशन कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

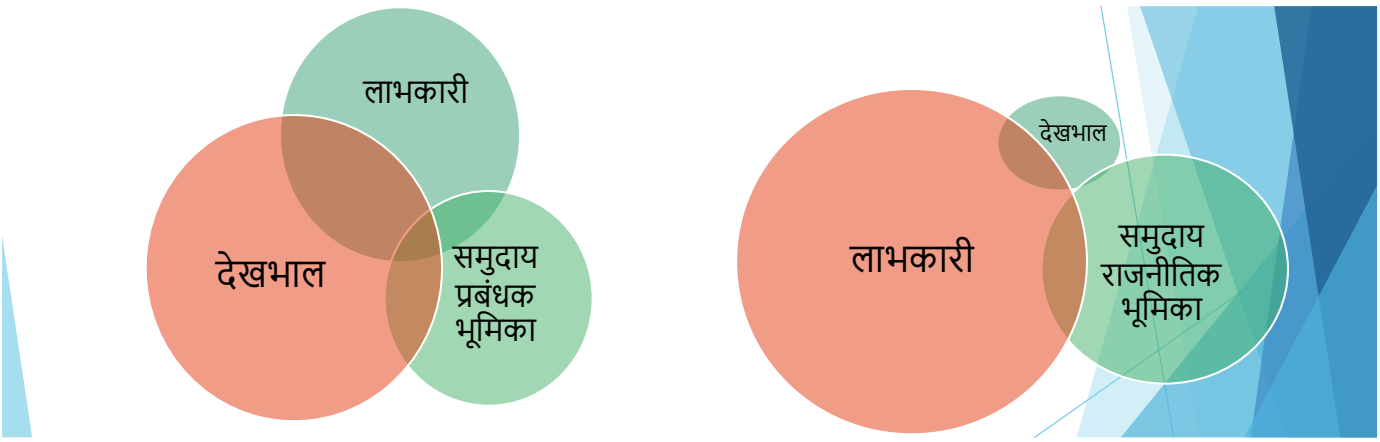

जेंडर एकीकरण और परिचालनात्मक रणनीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक स्लाइड

दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संसाधन प्रकोष्ठ (डीएवाई-एनआरएलएम आरसी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने जेंडर एकीकरण और परिचालनात्मक रणनीति की तैयारी पर असम, ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिशन कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय (समानांतर बैच) ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

एनआरएलएम ग्रामीण गरीब महिलाओं को सामान्य रूप से एकजुट करता है और शोषण स्थितियों / व्यवसायों (जैसे एकल महिला, तलाकशुदा, अलग, हिंसा से बचे, हिंसाग्रस्त महिलाओं, देवदासियों, एचआईवी पॉजिटीव महिलाओं, आदि) में महिलाओं तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से जुटाता है। अधिकांश महिलाएँ एसएचजी के माध्यम से एलआरएलएम में लगी हुई हैं और इसने सामूहिकता के माध्यम से असमानताओं और संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करते हुए और महिलाओं के संस्थानों को मजबूत करके और उन्हें स्वयं सहायता समूहों में शामिल करके महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है।

एनआरएलएम का मानना है कि जेंडर मुख्यधारा को अपने ढांचे, प्रणालियों, संस्थानों और प्रक्रियाओं में सततयोग्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, जिनका समुदाय के जीवन संकेतकों की गुणवत्ता पर सीधा / अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जेंडर असमानता अभी भी घरों, कार्यस्थलों और समाज में बड़े पैमाने पर मौजूद है और शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों और कौशल-निर्माण पर पहुंच और नियंत्रण और उपलब्धि में असमानता, श्रम के असमान विभाजन, आदि को भी ध्यान में रखते हुए मौजूद है। विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एनआरएलएम संसाधन सेल राज्यों के मिशन कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन की समान पहुंच के महत्व के बारे में मिशन के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य मिशन के कर्मचारियों में एनआरएलएम के विभिन्न घटकों जैसे आजीविका, संस्था निर्माण क्षमता निर्माण (आईबीसीबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), आदि में जेंडर के एकीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना था, ताकि प्रभावी पहुंच के लिए एसएचजी सदस्यों का समर्थन किया जा सके। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए अधिकारों और अधिकारों का उपयोग करें।

डॉ. वाई. रमणा रेड्डी, निदेशक, एनआरएलएम संसाधन कक्ष, एनआईआरडीपीआर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम असम, ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम 4 -30 जनवरी, 2021 से समानांतर रूप से बैच-वार आयोजित किए गए थे। कुल 64 बैच आयोजित किए गए और प्रत्येक बैच दो दिनों तक चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को जेंडर के एकीकरण जैसे कि जेंडर और लिंग का अंतर, जेंडर का समाजीकरण, श्रम का जेंडर तौर पर विभाजन, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक संस्थाओं तक पहुंच, नियंत्रण और एनआरएलएम में संस्थागत तंत्र आदि के बारे में मुख्यधारा में जेंडर का एकीकरण की जानकारी दी गई।

प्रमुख चर्चा बिंदु महिलाओं में अधिकारों, निर्णय लेने वाले निकायों, धन और अन्य परिसंपत्तियों तक पहुंच की कमी और कम आय वाले हैं। इस प्रकार यह पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप हुआ, जिसे जेंडर अंतराल के रूप में जाना जाता है और पितृसत्ता के माध्यम से जारी यह असमानता हिंसा को बढ़ावा देती है। जेंडर अंतर को कम करने के लिए जेंडर रुचि, व्यावहारिक जेंडर की आवश्यकता और रणनीतिक जेंडर की आवश्यकता जैसे मुद्दों को समझा जाना चाहिए। लैंगिक असमानताएँ श्रम के जेंडर विभाजन और समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति से उत्पन्न होती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने मिशन के कर्मचारियों को व्यावहारिक जेंडर आवश्यकताओं के बारे में प्रेरित किया, अर्थात्, शिक्षा और संपत्ति की समान पहुंच, पानी का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा, आय-अर्जित करने का अवसर, घर के भीतर बुनियादी सेवाएं, परिवार के भोजन का प्रावधान आदि।

घर के भीतर जेंडर भूमिकाओं की रूढ़िवादिता असमानता लाती है, विशेष रूप से महिलाओं की व्यावहारिक लैंगिक ज़रूरतें, क्योंकि वे महिलाओं पर उनकी ज़िम्मेदारी के रूप में पनपती हैं, हालांकि, रणनीतिक जेंडर ज़रूरतों में श्रम उन्मूलन के लैंगिक वर्गीकरण का उन्मूलन, घरेलू श्रम और बच्चों का बोझ शामिल है। भेदभाव के संस्थागत रूपों को हटाना जैसे कि जमीन या संपत्ति पर अधिकार, ऋण और अन्य संसाधनों तक पहुंच, बच्चे पैदा करने की पसंद की स्वतंत्रता, पुरुष हिंसा के खिलाफ उपाय और महिलाओं पर नियंत्रण।

राज्यों जैसे असम (486), ओडिशा (227), कर्नाटक (265), बिहार (514), आंध्र प्रदेश (640), तेलंगाना (900) से कुल 3,032 मिशन कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

एनआईआरडीपीआर ने मनाया 72 वां गणतंत्र दिवस

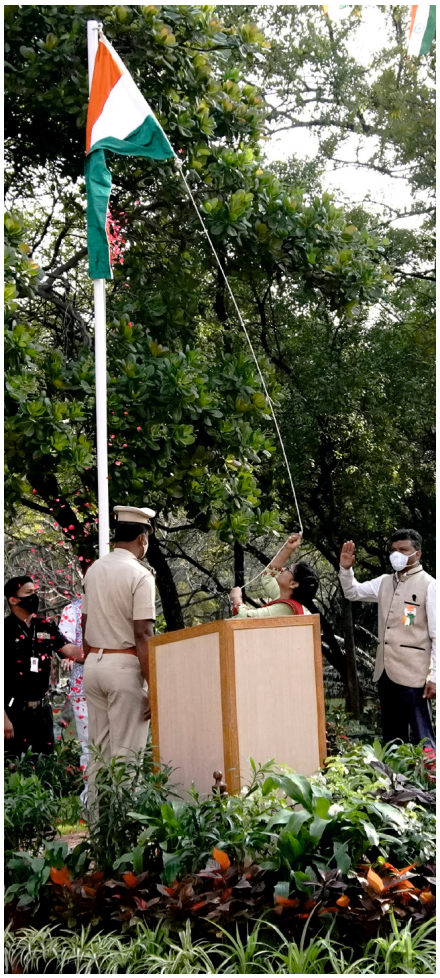

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक ने 72 वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया

(3, 4, 5 वें से बाएं से दाएं) लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन), श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक और श्री शशि भूषण, वित्तीय सलाहकार और निदेशक, एनआईआरडीपीआर के साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेता

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने 26 जनवरी, 2021 को कैंपस में 72 वां गणतंत्र दिवस मनाया। समारोह की शुरुआत श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा ध्वजारोहण फहराते हुए तथा सभी के द्वारा राष्ट्रगान से हुई । इसके बाद संस्थान के सुरक्षा गार्डों की सलामी हुई इसके बाद श्रीमती राधिका रस्तोगी ने इस अवसर पर सभा का स्वागत और शुभकामनाएं देते हुए अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत इन सभी वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जीवित रहा है। "उसी तरह, एनआईआरडीपीआर वर्षों से देश के विकास में योगदान दे रहा है। भारत में ग्रामीण आबादी आज शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं से वंचित है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों और वन की कीमत पर विकसित किया जा रहा है। दोनों क्षेत्रों को संतुलित करने के लिए रूर्बन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश कर सकते हैं।

समारोह के एक भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था और विजेताओं के लिए पुरस्कार श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, श्री शशि भूषण, एफए और निदेशक वित्त, लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन) द्वारा वितरित किए गए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य लोगों में केंद्र प्रमुख और संकाय सदस्य, एनआईआरडीपीआर के कर्मचारी और छात्र शामिल थे।

-सीडीसी पहल

कोविड-19 सहायता पैकेज (सीएपी) के तहत ओएलएम का मामला अध्ययन

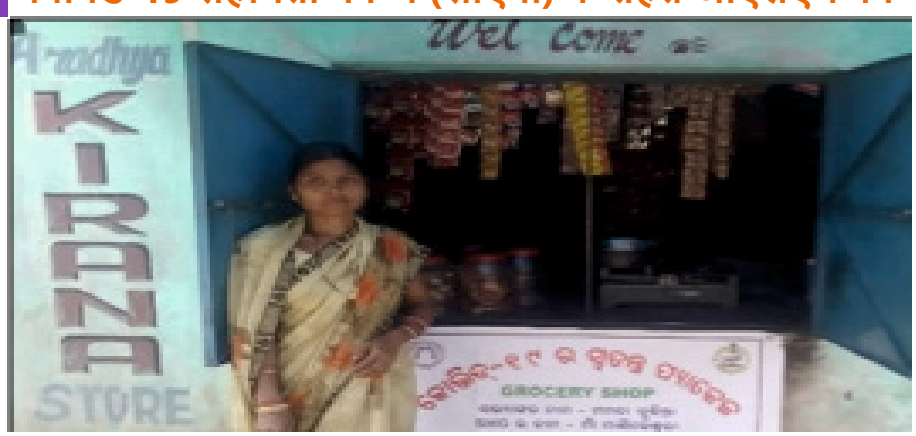

श्रीमती ममता बुधिया अपने किराने की दुकान पर

कोविड-19 महामारी ने राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। वर्तमान कोविड स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न वित्तीय सहायता पैकेज ग्रामीण आबादी के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप ओडिशा आजीविका मिशन (ओएलएम) के तहत डिज़ाइन किए गए हैं। ओडिशा देश का पहला राज्य था जिसने ग्रामीण गरीबों के लिए विविध और लाभकारी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरूआत की।

कई ग्रामीण महिला उद्यमियों को इस मुश्किल समय के दौरान उनका समर्थन करने के लिए कोविड-19 सहायता कार्यक्रम के तहत ऋण दिया गया था। श्रीमती ममता बुधिया सीएपी के लाभार्थियों में से एक हैं। श्रीमती ममता बुधिया परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति औसतन थी। छः सदस्यों वाले परिवार ने कृषि भूमि और एक किराने की दुकान के छोटे पैच की खेती के माध्यम से अस्तित्व के लिए सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। वह वर्ष 2018 में एक एसएचजी में शामिल हुई थी जब ओएलएम

हस्तक्षेप शुरू किया गया था। एसएचजी में शामिल होने के बाद, उसने बचत के मूल्य और बचत में विभिन्न तरीकों का एहसास किया। बाद में उसने एसबीआई की शाखा में बैंक खाता खोला और एसएचजी समूह में कुछ पैसे बचाए। एसएचजी समूह के रूप में वह बैंक ऋण का लाभ उठाने का एक हिस्सा था, उसने किराने की दुकान में ऋण राशि का अपना हिस्सा निवेश किया। उन्होंने किराने की दुकान का प्रबंधन किया और उनके पति कृषि कार्य में शामिल थे और अपनी किराने की दुकान के लिए विभिन्न विक्रेताओं से थोक वस्तुओं की खरीद कर रहे थे । कोविड-19 महामारी के कारण, किराने की दुकान से आय रु. 400 से रु. 500 घटकर रु. 200 प्रति दिन हो गई और दो महीने की अवधि के लिए सरकारी मानदंडों के पालन में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा, उसने अपनी सारी बचत कपास की खेती में लगा दी। जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बेपटरी हो गई और दोनों छोरों का मिलना मुश्किल हो गया।

इस बीच, श्रीमती ममता को ओएलएम द्वारा शुरू की गई सीएपी ऋण के बारे में एसएचजी समूह से पता चला जिसके माध्यम से उन्हें कुछ वित्तीय सहायता मिल सकती है। उसने अपने महासंघ एमबीके (विस्तार) से संपर्क किया और जीपीएलएफ (विस्तार) के चुनाव आयोग के सदस्य को प्रस्ताव दिया। बाद में, उसे जीपीएलएफ से 50,000 / - रुपये की राशि एक कैप ऋण के रूप में मिली जिसे किराने की वस्तुओं की खरीद में लगाया गया था। अब बिक्री बढ़ गई है और वह रुपये 500 प्रति दिन कमाकर अच्छा लाभ कमा रही है। श्रीमती ममता आगे कुछ फैंसी आइटम जोड़कर अपनी दुकान का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। जीपीएलएफ और ओएलएम की अंतरिम वित्तीय सहायता ने उसे कोविड - 19 महामारी के दौरान आय को फिर से स्थापित करने और परिवार की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में मदद की।

श्री अनुराग कुशवाहा
युवा पेशेवर,
ओडिशा आजीविका मिशन

संपूर्ण भारत में मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना की एक रूपरेखा

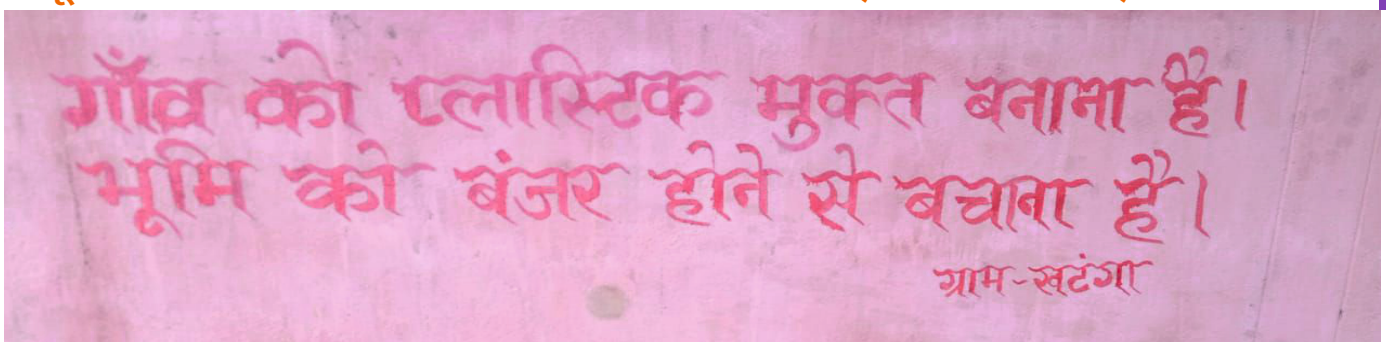

प्लास्टिक के उपयोग के उन्मूलन को प्रोत्साहित करने वाली एक दीवार लेखन

पृष्ठभूमि

भारत में पंचायती राज प्रणाली ने पिछले 2 दशकों में आरजीएसवाई, बीआरजीएफ (सीबी घटक), आरजीपीएसए और आरजीएसए के तहत कई क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को देखा। 2018 में, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने आरजीएसए के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए निरंतर समर्थन के प्रावधान के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर संशोधित दिशानिर्देश प्रकाशित किए।

इसके बाद 2018 और 2019 में जीपीडीपी के लिए दो क्रमिक जन योजना अभियान हुए; लेकिन देश में बहुत कम जीपी को गुणवत्ता वाले जीपीडीपी तैयार करने और लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता प्राप्त करना बाकी है और जीपीडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए योजनाओं की निगरानी करें। समस्या के समाधान की तलाश में, विभिन्न स्तरों पर आयोजित बातचीत के आधार पर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने कुछ मॉडल जीपी बनाने के लिए 100 + क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए एक कार्य अनुसंधान परियोजना को प्रारंभ करना उपयुक्त समझा कि क्लस्टर भारत भर में अन्य सभी जीपी को प्रेरित करने के लिए मॉडल जीपी का पालन करने और अपने क्षेत्रों में अच्छी प्रथाओं को दोहराया जा सके ।

100 + क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए कार्य अनुसंधान परियोजना का पहला चरण

एनआईआरडीपीआर ने असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे पांच राज्यों में 59 मॉडल जीपी क्लस्टर के निर्माण के लिए अगस्त 2019 में कार्य अनुसंधान परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया।

इन समूहों के तहत जीपी की कुल संख्या 202 है। एनआईआरडीपीआर को अप्रैल 2010 में ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे छह और राज्यों में 343 जीपी को कवर करते हुए अन्य 66 जीपी क्लस्टरों में कार्य अनुसंधान परियोजना का विस्तार करना था। लेकिन कोविड-19 के कारण, विस्तार नहीं हो सका। एनआईआरडीपीआर द्वारा इस परियोजना को कई कॉर्पोरेट्स (सीएसआर पहल के माध्यम से) और सोझेदार संस्थानों जैसे आर्ट ऑफ़ लिविंग फाउंडेशन, मिशन समृद्धि, पारिस्थितिक सुरक्षा फाउंडेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एसईआरए ट्रस्ट (एनआरआई) टाटा स्टील और आईटीसी से वित्तीय और / या तकनीकी सहायता से लागू किया जाएगा। झारखंड के मामले में, इसे राज्य आरडी और पंचायती राज विभाग से वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है। उम्मीद है, कोविड-19 समस्या को कम करने के बाद, शेष राज्यों में कार्य अनुसंधान परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा, इस प्रकार कुल 11 राज्यों में 545 जीपी को कवर करते हुए 125 क्लस्टर की कुल संख्या तक पहुंच जाएगी।

एमओपीआर समर्थन के साथ 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए द्वितीय चरण परियोजना

100+ क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए कार्य अनुसंधान परियोजना के तहत जो भी थोड़ी सफलता मिल सकती है, उसका अवलोकन करते हुए, एमओपीआर ने भारत भर में सभी राज्यों (पंजाब और आंध्र प्रदेश को छोड़कर) और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान-निकोबार द्वीप समूह,

सामाजिक जागरूकता फैलाने के भाग के रूप में दीवार पर उद्धरण लिखता हुआ एक ग्रामीण

दादरा नगर हवेली और दमन- दीव, पुडुचेरी, जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में 1105 जीपी को कवर करते हुए 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए एक बड़ी परियोजना का समर्थन करने के लिए आगे आया। चरण -2 के तहत यह परियोजना एनआईआरडीपीआर द्वारा 2020-22 तक तीन प्रमुख भागीदारों - (क) एमओपीआर (ख) राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश (सी) यूएनडीपी के समर्थन से कार्यान्वित की जाएगी। एमओपीआर ने 23 जून, 2020 को आयोजित सीईसी की बैठक के माध्यम से इस परियोजना के लिए केवल रु. 3,08,40,000 की राशि को मंजूरी दी, जिसका उपयोग एनआईआरडीपीआर द्वारा 2020-21 और 2021-22 तक किया जाएगा। इस प्रकार, जब परियोजना का कार्यान्वयन सभी समूहों में शुरू होता है, तो इकाइयों की कुल संख्या 555 जीपी और 150 क्लस्टर वाले 250 क्लस्टर होंगे, जिसमें 1105 जीपी (125 + 250 = 375 क्लस्टर वाले 545 + 1105 = 1650 जीपी) होंगे।

मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य

परियोजना का लक्ष्य 250 आदर्श जीपी क्लस्टर बनाने के लिए समग्र और सतत विकास प्राप्त करना है - जीपी की संस्थागत मजबूती को बढ़ाना और सूट का पालन करने के लिए अन्य जीपी को प्रेरित और उत्प्रेरित करने के लिए सच्ची भावना से जीपीडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन में जीपी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन करने द्वारा गुणात्मक जीपीडीपी को सक्षम बनाना। उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए स्व-सरकार के संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए परियोजना जीपी को गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और प्रेरित करना।

(ख) 'यंग फैलो' 'क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन' और 'बीकन पंचायत लीडर्स' के माध्यम से प्रोजेक्ट जीपी को समर्थन देना - जीपीडी की संस्थागत क्षमताओं को विकसित करना और गुणात्मक तरीके से जीपीडीपी को तैयार करना, लागू करना और उसकी निगरानी करना।

(ग) नियोजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और विभिन्न हितधारकों की योजनाओं और प्रयासों के अभिसरण की सही समझ प्रदर्शित करना।

(घ) अभ्यास के स्कूलों के रूप में परियोजना जीपी का समर्थन करना और धीरे-धीरे देश भर में अन्य जीपी को मॉडल के रूप में अनुपालन करने तथा प्रेरित करने के लिए बीकन जीपी के रूप में उभारना।

(इ) गत 3 वर्षों में निवेश पर बड़े सामाजिक / आर्थिक आय की सुविधा देना।

प्रमुख परियोजना हस्तक्षेप

जैसा कि डिजाइन किया गया है, प्रमुख परियोजना हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

(क) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के लिए 12 राज्य कार्यक्रम समन्वयकों (2-3 राज्यों के लिए @ 1) की तैनाती; परियोजना जीपी को अनुभव समर्थन प्रदान करने के लिए 250 योग्य युवा फेलो @ 1 प्रति क्लस्टर; 250 क्लस्टर स्तर संसाधन व्यक्ति @ 1 प्रति समूह एसएचजी और उनके संघों के समर्थन के साथ सामुदायिक एकत्रीकरण के लिए; 125 बीकन पंचायत नेताओं @ 1 प्रति दो समूहों को जीपी के लिए सलाह और प्रेरक सहायता प्रदान करना।

(ख) सभी संबंधित मुद्दों पर परियोजना कर्मचारियों का गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।

(ग) मुख्य रूप से एसआईआरडी से राज्य और जिला स्तर के मास्टर ट्रेनरों की गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।

(घ) जीपी, सहभागी नियोजन और मिशन अंत्योदय, ई-ग्राम स्वराज और स्थानिक योजना के संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर जीपी और सीआरपी के कार्यकारियों और ईआरएस को गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और अनुभवपरक समर्थन।

(इ) राज्य के अंदर और बाहर जीपी की ईआरएस के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया प्रदर्शनी दौरा (समृद्धि यात्रा)।

(च) परियोजना जीपी में स्थानिक योजना।

(छ) प्रत्येक परियोजना जीपी में एक कुशल योजना का विकास।

(ज) मूल्यांकन, परियोजना तैयारी, संस्था निर्माण, रोल आउट और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना, पोस्ट-कोविड-19 स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करना

(झ) राज्य, जिला और ब्लॉक अधिकारियों, मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों, एसएचजी महासंघों, राजनीतिक नेताओं, और अन्य लोगों के बीच कॉर्पोरेट / सीएसओ / गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण।

(ट) संगठनात्मक विकास का मानचित्रण और जीपी की क्षमता का बेंचमार्किंग

(ठ) 'पंचायतों के मित्र' के रूप में परियोजना जीपी का समर्थन करने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों का विकास

(ड) परियोजना हस्तक्षेप का कुशल प्रबंधन और निगरानी

(ढ) सीखे गए पाठों के प्रसार के लिए प्रक्रियाओं, आउटपुट और परिणामों का निरंतर प्रलेखन

(ण) सुधारात्मक उपायों के लिए बाहरी संस्थानों के माध्यम से परियोजना का वार्षिक मूल्यांकन।

प्रमुख परियोजना साझेदार

परियोजना को वास्तव में अभिसरण तरीके से इसके कार्यान्वयन में कई साझेदारी के साथ डिजाइन किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(क) एमओपीआर इस परियोजना के लिए अनुमोदन प्राधिकारी है और, दो साल के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है 2020-21 और 2021-22 (यानी आरजीएसए के अंतिम वर्ष तक)। व्यापक नीति समर्थन के अलावा, एमओपीआर को आरजीएसए के केंद्रीय घटक से मानव संसाधन की 100 प्रतिशत लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना है, जो कुल परियोजना लागत का 44.02 प्रतिशत है।

(ख) एनआईआरडीपीआर ने एमओपीआर से अनुरोध और प्रोत्साहन के आधार पर इस परियोजना को डिजाइन किया। 125 मॉडल जीपी क्लस्टर्स के लिए चल रहे कार्य अनुसंधान परियोजना के साथ-साथ, एनआईआरडीपीआर (पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केन्द्र) के माध्यम से इस परियोजना को लागू करेगा और एमओपीआर, राज्यों, यूएनडीपी और अन्य संस्थानों के एक विस्तृत श्रृंखला से निगरानी करेगा। एनआईआरडीपीआर इस

परियोजना के तहत कुछ गतिविधियों को लागू करने वाली राज्य मशीनरी साझेदार संस्थान और परियोजना कर्मचारी की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) की देखभाल अपने सामान्य प्रशिक्षण कोष से, इसके वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के हिस्से के रूप में कुल परियोजना लागत का 5.62 प्रतिशत से करेगा।

(ग) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग और राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईपीआरडी) / राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) / आरजीएसए और जीपीडीपी के लिए अन्य नोडल संस्थान एनआईआरडीपीआर के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत लागू करेगा और कुछ गतिविधियों की लागत वहन करेगी। आरजीएसए (केंद्रीय + राज्य के शेयरों) के तहत निर्धारित गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाने वाला कुल खर्च कुल परियोजना लागत का 39.78 प्रतिशत है।

(घ) निगरानी, संचार, वकालत, नवीन प्रौद्योगिकी के लिए प्रणालियों के विकास के लिए यूएनडीपी को चयनित राज्यों में 50 क्लस्टरों का समर्थन करना है और देश भर में पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता संस्थान के रूप में कार्य करना है। उपकरण आदि, प्रक्रियाओं का निरंतर प्रलेखन, अच्छी प्रथाओं, आउटपुट और परिणाम और परियोजना का मूल्यांकन एक तीसरी पार्टी द्वारा किया जाना है - प्रत्येक वर्ष के अंत तक इन गतिविधियों के लिए, यूएनडीपी को कुल परियोजना लागत का 10.59 प्रतिशत वहन करने की उम्मीद है।

कई साझेदारी वाली यह परियोजना इतने बड़े पैमाने पर अपनी तरह की पहली परियोजना है और इसे मिशन मोड पर आउट-ऑफ-द-बॉक्स तरीके से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य यह है कि इसे आम तौर पर न होने देने के लिए सुविधा प्रदान की जाए। इसलिए, सभी भागीदारों को अनुमोदित परियोजना के डिजाइन और इस परियोजना कार्यान्वयन योजना के बाद, अग्रानुक्रम में और सही समन्वय के साथ अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

सहायक संस्थायें

जैसा कि डिजाइन किया गया है, इस परियोजना को नीचे दिए गए अनुसार कई सहायक संस्थाओं के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा, जिन्होंने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण विकास में योगदान दिया है:

गाँव की महिलाएँ अपने आसपास की सफाई करती हैं

(क) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीआरआई-एसएचजी अभिसरण के लिए)

(ख) जिला, ब्लॉक और जीपी स्तर पर अपने अधिकारियों के माध्यम से कार्य करने के लिए लाइन विभाग

(ग) आर्थिक विकास के लिए उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्थानीय क्रेडिट संस्थान

(घ) मिशन समृद्धि (आईटी समर्थन के लिए समृद्धि यात्रा नामक संरचित एक्सपोज़र विज़िट)

(ड़) आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के तहत व्यक्ति विकास केंद्र भारत
(मोटिवेशन, लीडरशिप, नो-कॉस्ट स्वैच्छिक कार्यों आदि पर प्रशिक्षण के लिए)

(च) पारिस्थितिक सुरक्षा फाउंडेशन (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वाटरशेड विकास तकनीकों, स्थानिक योजना और योजना के लिए देशव्यापी समृद्ध डेटाबेस के माध्यम से आर्थिक विकास पर प्रशिक्षण के लिए)

(छ) शासन लैब (जीपी संगठन विकास और जीपी की क्षमताओं की बेंचमार्किंग के लिए)

(ज) मधुकर आजीविका फाउंडेशन (आर्थिक विकास मॉडल के निर्माण के लिए)

(झ) अंतिम प्रबंधन समाधान, भारत (स्वयंसेवकों के रूप में युवाओं के विकास पर प्रशिक्षण के लिए)

(ट) नेहरू युवा केंद्र (स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए)

(ठ) हम भारत के लोग (संवैधानिक अधिकारों पर प्रशिक्षण के लिए)

(ड) यूनिसेफ (बाल-मैत्री जीपी)

(ढ) सीएसओ / स्थानीय एनजीओ / स्थानीय सीबीओ जिनमें एसएचजी और उनके फेडरेशन्स / लोकल यूथ क्लब / वालंटियर्स आदि शामिल हैं।

(ण) मिशन में शामिल होने के लिए तैयार कोई भी अन्य अच्छी संस्था।

मुख्य उत्पाद

(क) संस्थागत रूप से मजबूत जीपी
(ख) कार्यात्मक स्थायी समितियाँ
(ग) ईआर और जीपी के कार्यकारियों की क्षमताएं
(घ) कार्यालय, कार्यों और खरीद का कुशल प्रबंधन
(ड़) जीपी के अपने राजस्व स्रोत में वृद्धि।
(च) प्रत्येक जीपी में एक डेटाबेस
(छ) योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में लोगों की बड़े पैमाने पर भागीदारी।
(ज) सूचित और परिवर्तित नागरिक (लाभार्थियों से अभिनेताओं तक)
(झ) हितधारकों के साथ औपचारिक परामर्श बैठक
(ट) प्रत्येक जीपी में एक कौशल योजना
(ठ) स्वैच्छिक कार्यों के माध्यम से समुदायों द्वारा संपत्ति का सृजन और रखरखाव
(ड) प्रतिगामी आर्थिक विकास मॉडल
(ढ) मजबूत पीआरआई-एसएचजी अभिसरण।
(ण) बेहतर सामाजिक समावेश।
(त) समुदायों द्वारा मुफ्त स्वैच्छिक कार्रवाई।
(थ) कौशल के लिए नई तकनीकों का अनुप्रयोग।
(द) बढ़ी हुई जवाबदेही और पारदर्शिता।
(ध) एसडीजी- अनुरूप, पर्यावरण-मित्र, बाल-मित्र और जेंडर मात्र जीपी
(न) नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार

अब तक प्रगति

एमओपीआर द्वारा अनुमोदित परियोजना डिजाइन को यूएनडीपी, 12 अन्य साझेदार संस्थानों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था, जो कि काफी पहले से कार्यान्वयन अभियान में शामिल हो गए हैं। इस बीच, एनआईआरडीपीआर में परियोजना टीम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(क) परियोजना के प्रबंधन और निगरानी के लिए 8 (17 में से) कर्मचारियों के साथ एनआईआरडीपीआर में एक पीएमयू का गठन किया गया है

(ख) 510 परियोजना कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अभियान 24 जून, 2020 को शुरू किया गया था। लेकिन लगभग 30,000 उम्मीदवारों में से योग्य उम्मीदवारों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के बाद भी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की आरक्षण नीति के गैर-अनुपालन के खिलाफ उठाए गए कुछ मुद्दों के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

(ग) पीएमयू स्टाफ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बातचीत की और एनआईआरडीपीआर के साथ भागीदारी करने के लिए विभिन्न संगठनों की परियोजनाओं और भूमिकाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्पष्ट किया।

(घ) राज्य नोडल अधिकारियों सहित कुल 348 अधिकारी, राज्य स्तर के मास्टर प्रशिक्षक और जिला स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों को परियोजना की प्रभावशीलता के बारे में उन्मुख करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए तीन दिनों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था।

(ड़) एक मसौदा परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) अगस्त 2020 के मध्य में परियोजना की शुरुआत के समय के रूप में इंगित करने के लिए तैयार की गई थी। चूंकि भर्ती अभियान पूरा नहीं हो सका, इसलिए ड्राफ्ट पीआईपी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

(च) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गठित 250 जीपी क्लस्टरों को एनआईआरडीपीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समर्थन से अंतिम रूप दिया था।

(छ) एनआईआरडीपीआर और यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से परियोजना के लिए एक निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम ढांचा विकसित किया है।

(ज) एनआईआरडीपीआर के पीएमयू ने प्रासंगिक डेटा (मिशन अंत्योदय रिपोर्ट, एमए गैप विश्लेषण रिपोर्ट और नवीनतम जीपीडीपी) एकत्र किया है जो जीपी के 250 क्लस्टर डेटा के तहत 1,105 जीपी से संबंधित है।

(झ) पीएमयू अब प्रोजेक्ट जीपी द्वारा युवा अधिसदस्य और क्लस्टर स्तर स्त्रोत व्यक्ति के अनुभव समर्थन के साथ लगभग 30 हस्तक्षेप पर परिचालन दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।

परियोजना की संभावना का उल्लेख

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एक भर्ती अभियान जून 2020 में आयोजित किया गया था, लेकिन भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की आरक्षण नीति के गैर-अनुपालन के खिलाफ उठाए गए कुछ मुद्दों के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने निर्देश दिया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुपालन में परियोजना कर्मचारी (510) के पदों को भरने के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए जाए।

इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। यह उम्मीद की जा सकती है कि परियोजना कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया फरवरी 2021 के अंत तक पूरी हो जाएगी और परियोजना कर्मचारी उस समय के तुरंत बाद क्षेत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं।

डॉ. दिलीप पाल
परियोजना टीम लीडर
250+ के लिए कार्य अनुसंधान परियोजना
क्लस्टर
नआईआरडीपीआर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका